छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्र.एफ–13–5/2019/आ.प्र./1–3   अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29/5/2019
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
छत्तीसगढ़

विषयः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य निर्देश।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 30.4.2019.

———————

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए भारत सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019–Estt(Res), दिनांक 31.01.2019 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार इस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संदर्भित आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

2/ इस विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु केवल सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसमें आवेदन के प्रारूप एवं प्रक्रिया के संबंध में स्थिति दर्शित न होने के कारण जिला कार्यालयों में उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विभिन्न कठिनाईयां आ रही हैं। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को **"आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र"** प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–एक)** में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदकों को आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत करने होंगे।
3. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो वर्तमान में आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रचलित है।
4. प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व उद्घोषणा एवं दावा आपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदारों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत ही उक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करने के विरूद्ध आवेदक द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील तथा संभागीय आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

क्रमशः....2

7. आवेदन के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों/दस्तावेजों इत्यादि की समुचित जांच व परीक्षण जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाए एवं स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मिथ्या साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होने पर जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी होने पर सक्षम प्राधिकारी के विरूद्ध की जाती है।
8. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन कमांक 36039/1/2019 Estt (Res), दिनांक 31.1.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 4.1 में आय एवं सम्पत्ति के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं कीमीलेयर योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) से कम है, उनकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में की जाएगी। आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र में आय, आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्त्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे एवं अन्य स्त्रोतों से हुई आय शामिल होगी। ऐसे उम्मीदवारों की पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास उक्त ज्ञापन की कंडिका 4.1 में उल्लिखित कोई भी सम्पत्ति होगी, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो।
9. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का समुचित रूप से परीक्षण/सत्यापन किया जाकर, आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 13–5/2019/आ.प्र./1–3 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29/5/2019
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
6. समस्त निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर
11. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़,
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर,
14. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।

कमशः....3

15. संचालक, राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), रायपुर की ओर भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019–Estt(Res), दिनांक 19.01.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 की छायाप्रति सहित सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **http://www.gad.cg.gov.in/** पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

स्व–प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
नवीनतम फोटो

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)/तहसीलदार,

....,

जिला...(छ.ग.)।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/मेरी पुत्री को केन्द्र सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति हेतु/शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:–

1.	आवेदक का पूरा नाम	(हिन्दी में).. (अंग्रेजी में)..
2.	आवेदक के पिता का पूरा नाम	(हिन्दी में).. (अंग्रेजी में)..
3.	हितग्राही का नाम (जिसके लिए प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है)	(हिन्दी में).. (अंग्रेजी में)..
4.	हितग्राही की जन्मतिथि	अंकों में.. शब्दों में..
5.	हितग्राही विवाहित है अथवा अविवाहित	....
6.	क्या हितग्राही छ.ग. राज्य का स्थानीय निवासी है ?	....
7.	आवेदक/हितग्राही का पूरा पता (ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नं., तहसील एवं जिला सहित)	**अ. वर्तमान पता–** ग्राम...............................पोस्ट आफिस............................... तहसील...............................जिला............................... राज्य...............................पिन कोड............................... **ब. स्थाई पता–** ग्राम...............................पोस्ट आफिस............................... तहसील...............................जिला............................... राज्य...............................पिन कोड...............................
8.	हितग्राही की जाति (उपजाति सहित)	जाति...............................उपजाति...............................
9.	क्या हितग्राही अनारक्षित वर्ग का है? (हां/नहीं)	....

क्रमशः....2

10. **पिछले वित्तीय वर्ष में परिवार की कुल आय की जानकारी :–**

क्र.	परिवार के सदस्यों के नाम	मुखिया से संबंध	आयु	कुल आय	आय का स्त्रोत (वेतन/कृषि/व्यवसाय/कारोबार/भूमि/मकान/अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय की जानकारी पृथक–पृथक दी जाए)
1.					
2.					
3.					

11 **पिछले वित्तीय वर्ष में परिवार के उक्त सदस्यों की सम्पत्ति की जानकारी :–**

क्र.	परिवार के सदस्यों का नाम	सम्पत्ति का विवरण स्थान/पता एवं सहित			
		कृषि भूमि (रकबा एकड़ में एवं किस राज्य में स्थित है)	आवासीय फ्लैट/मकान (क्षेत्रफल वर्ग फुट में एवं किस राज्य में स्थित है)	अधिसूचित नगर पालिकाओं में धारित आवासीय भू–खण्ड (क्षेत्रफल वर्ग गज में एवं किस राज्य में स्थित है)	अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्ड (क्षेत्रफल वर्ग गज में एवं किस राज्य में स्थित है)
1.					
2.					
3.					

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची

(1) आधार कार्ड/अन्य फोटोयुक्त परिचय पत्र की छायाप्रति,
(2) जन्मतिथि की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
(3) छ.ग. के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
(4) वेतन से आय के संबंध में नियोक्ता का प्रमाण पत्र (व्यवसायी/शासकीय सेवकों के लिए गत वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति),
(5) भूमि/मकान से आय के संबंध में अनुबंध पत्र की छायाप्रति/स्वघोषणा पत्र,
(6) अन्य स्त्रोतों से आय के संबंध में प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र,
(7) आवासीय फ्लैट/मकान की रजिस्ट्री की छायाप्रति
(8) कृषि भूमि के संबंध में बी–1 खसरा/ऋण–पुस्तिका की छायाप्रति,
(9) आवासीय भू–खण्ड की रजिस्ट्री की छायाप्रति
(10) पासपोर्ट साईज एक अतिरिक्त फोटो।
(11) अन्य दस्तावेज जो सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाए।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है, तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी/शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है, उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
तथा नाम

दिनांक– ....

स्थान– ....

F. No.36039/1/2019-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi
19th January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India

Reference is invited to Ministry of Social Justice and Empowerment O.M. No. F.No.20013/01/2018-BC-II dated 17.1.2019 on the above mentioned subject, which, inter-alia, reads as under:-

"1. In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i. 5 acres of Agricultural Land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after

Gyanendra Tripathi
19/1/2019

carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/ UT.

....

5. Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DOPT and Ministry of HRD respectively."

2. In pursuance of the above Office Memorandum, it is hereby notified that 10% reservation would be provided for Economically Weaker Sections (EWSs) in central government posts and services and would be effective in respect of all Direct Recruitment vacancies to be notified on or after 01.02.2019.

3. Detailed Instructions regarding operation of roster and procedure for implementation of EWS reservation will be issued separately.

Gyanendra Tripathi 19/01/2019
(Gyanendra Dev Tripathi)
Joint Secretary to the Government of India

To

1. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Financial Services, New Delhi
3. Department of Public Enterprises, New Delhi
4. Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhavan, New Delhi
5. Secretary, Ministry of Human Resources Development, Shastri Bhavan, New Delhi.
6. Supreme Court of India/Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice President's Secretariat /Prime Minister's Office/ NITI Aayog
7. Union Public Service Commission / Staff Selection Commission
8. Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
9. National Commission for Scheduled Castes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
10. National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
11. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi
12. Office of the Comptroller and Auditor General of India
13. Information and Facilitation Center, DoPT, North Block, New Delhi.
14. Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi 110067
15. **NIC, DoPT – to upload the same on DoPT website.**
16. Hindi Section for providing a Hindi translation

No.36039/1/2019-Estt (Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
dated the 31st January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in direct recruitment in civil posts and services in the Government of India.

In continuation of this Department's Office Memorandum of even number dated 19.01.2019, the following instructions are issued in consultation with Ministry of Social Justice and Empowerment and Department of Legal Affairs regarding reservation for EWSs not covered under the reservation scheme for SCs/STs/OBCs in respect of direct recruitment in civil posts and services in the Government of India.

2. **QUANTUM OF RESERVATION**

The persons belonging to EWSs who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs shall get 10% reservation in direct recruitment in civil posts and services in the Government of India.

3. **EXEMPTION FROM RESERVATION:**

3.1 "Scientific and Technical" posts which satisfy all the following conditions can be exempted from the purview of the reservation orders by the Ministries/ Departments:

(i) The posts should be in grades above the lowest grade in Group A of the service concerned.

(ii) They should be classified as "scientific or technical" in terms of Cabinet Secretariat [OM No. 85/11/CF-61(1) dated 28.12.1961], according to which scientific and technical posts for which qualifications in the natural sciences or exact sciences or applied sciences or in technology are prescribed and the incumbents of which have to use that knowledge in the discharge of their duties.

G. Srinivasan

(iii) The posts should be 'for conducting research' or 'for organizing, guiding and directing research'.

3.2 Orders of the Minister concerned should be obtained before exempting any posts satisfying the above condition from the purview of the scheme of reservation.

4. CRITERIA OF INCOME & ASSETS:

4.1 Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs and whose family has gross annual income below **Rs. 8.00 lakh (Rupees eight lakh only)** are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application.

Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of the family income:-

i. 5 acres of agricultural land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

4.2. The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

4.3 The term "**Family**" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

5. INCOME AND ASSET CERTIFICATE ISSUING AUTHORITY AND VERIFICATION OF CERTIFICATE:

5.1 The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an Income and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and Asset Certificate issued by any one of the following authorities in the prescribed format as given in **Annexure-I** shall only be accepted as proof of candidate's claim as belonging to EWS: -

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendary

G. Srinivasan

Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and

(iv) Sub-Divisional Officer or the area where the candidate and/or his family normally resides.

5.2 The Officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT.

5.3 The crucial date for submitting income and asset certificate by the candidate may be treated as the closing date for receipt of application for the post, except in cases where crucial date is fixed otherwise.

5.4 The appointing authorities should, in the offer of appointment to the candidates claiming to be belonging to EWS, include the following clause :-

"The appointment is provisional and is subject to the Income and asset certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/false certificate."

The appointing authority should verify the veracity of the Income and asset certificate submitted by the candidate through the certificate issuing authority.

5.5 Instructions referred to above should be strictly followed so that it may not be possible for an unscrupulous person to secure employment on the basis of a false claim and if any person gets an appointment on the basis of such false claim, her/his services shall be terminated invoking the conditions contained in the offer of appointment.

6. EFFECTING RESERVATION - MAINTENANCE OF ROSTERS:

6.1 Department of Personnel and Training had circulated Office Memorandum No.36012/2/96-Estt(Res) dated July 2, 1997 regarding implementation of post based reservation roster. The general principles for making and operating post

G. Srinivasan

based reservation roster would be as per the principles laid down in the said Office Memorandum.

6.2 Every Government establishment shall now recast group-wise post-based reservation roster register for direct recruitment in accordance with format given in **Annexure II, III, IV and V**, as the case may be, for effecting 10% reservation for EWSs interpolating them with the SCs, STs and OBCs. While fixing roster point, if the EWS roster point coincides with the roster points of SCs/STs/OBCs the next available UR roster point has been allotted to the EWSs and also the principle of "squeezing" has been kept in view. While drawing up the rosters, the cadre controlling authorities may similarly "squeeze" the last points of the roster so as to meet prescribed 10% reservation.

6.3 Where in any recruitment year any vacancy earmarked for EWS cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog.

6.4 Persons belonging to EWS selected against the quota for persons with benchmark disabilities/ex-servicemen shall be placed against the roster points earmarked for EWS.

7. ADJUSTMENT AGAINST UNRESERVED VACANCIES:

A person belonging to EWS cannot be denied the right to compete for appointment against an unreserved vacancy. Persons belonging to EWS who are selected on the basis of merit and not on account of reservation are not to be counted towards the quota meant for reservation.

8. FORTNIGHTLY/ANNUAL REPORTS REGARDING REPRESENTATION OF EWS:

The Ministries/Departments shall send single consolidated fortnightly report including their attached/subordinate offices beginning from 15.2.2019 as per format at **Annexure-VI.**

From 01.01.2020, the Ministries/Departments shall upload data on representation of EWSs in respect of posts/services under the Central Government on the URL i.e. www.rrcps.nic.in as on 1st January of every year. All Ministries/Departments have already been provided respective usercode and password with guidelines for operating the URL.

G. Srivatsan

9. MAINTENANCE OF REGISTER OF COMPLAINTS BY THE GOVERNMENT ESTABLISHMENT:

9.1 Every Government establishment shall appoint a senior officer of the Department as the Grievance Redressal Officer.

9.2 Any person aggrieved with any matter relating to discrimination in employment against any EWS may file a complaint with the Grievance Redressal Officer of the respective Government establishment. The name, designation and contact details of the Grievance Redressal Officer may be displayed prominently on the website and in the office of the concerned establishment.

10. LIAISON OFFICER:

Ministries/Departments/Attached and Subordinate Offices shall appoint Liaison Officer to monitor the implementation of reservation for EWSs.

11. The above scheme of reservation will be effective in respect of all direct recruitment vacancies to be notified on or after 01.02.2019.

12. All the Ministries/Departments are requested to bring the above instructions to the notice of all appointing authorities under their control. In case of any difficulty with regard to implementation of the provisions of this OM, the concerned authorities may consult DOP&T through their administrative Ministry/Department.

Encl.: As above.

G. Srinivasan

(G. Srinivasan)
Director
Ph.No.011-23093074

To

(i) The Secretaries of all Ministries/Departments of the Govt. of India
(ii) Department of Financial Services, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi
(iii) Department of Public Enterprises, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
(iv) Railway Board, Rail Bhavan, Delhi.

(v) Supreme Court of India/ Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/ Prime Minister's Office/NITI Aayog
(vi) Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi
(vii) Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi
(viii) The Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Shastri Bavan, New Delhi
(ix) National Commission for Scheduled Castes, Lok Nayak Bhavan, New Delhi
(x) National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
(xi) National Commission for Backward Classes, Trikoot, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
(xii) Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
(xiii) Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi.
(xiv) Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi-110067.
(xv) All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and all attached/subordinate offices of this Ministry.

Copy to: Director, NIC, DOPT – with the request to immediately place this OM on the website of this Department (what's new tab) for information of all concerned.

G. Srinivasan

Annexure-I

Government of ....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. __________ Date: __________________

VALID FOR THE YEAR__________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ______________________ son/daughter/wife of _________________________ permanent resident of ____________________, Village/Street ______________ Post. Office _____________ District_________ in the State/Union Territory ________________ Pin Code__________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ________. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ______________________ belongs to the _______ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office______________
Name ________________________
Designation ________________

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

G. Srinivasan

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्र.एफ–13–5/2019/आ.प्र./1–3 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30/4/2019
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
छत्तीसगढ़

विषयः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019–Estt(Res), दिनांक 19.01.2019 द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रावधानित किया गया है एवं उक्त आरक्षण के संबंध में समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों की कंडिका–4 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए आय एवं सम्पत्तियों के संबंध में मापदंडों का निर्धारण किया गया है तथा कंडिका–5 में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.1.2019 के Annexure-1 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्धारित है। उक्त ज्ञापन इस विभाग की वेबसाईट **http://www.gad.cg.gov.in/** पर उपलब्ध है।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.1.2019 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/मापदंडों के अनुसार, **छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः....2

पृ.क. एफ 13–5/2019/आ.प्र./1–3 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30/4/2019

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
6. समस्त निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर
11. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़,
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर,
14. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
15. संचालक, राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), रायपुर की ओर भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019–Estt(Res), दिनांक 19.01.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 की छायाप्रति सहित सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **http://www.gad.cg.gov.in/** पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग